



भारत का गज़तापत्र

The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 102]

नई दिल्ली, बुधवार, 1 अगस्त 1984/श्रावण 10, 1906

No. 102] NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 1, 1984/SRAVANA 10, 1906

इस भाग में भिन्न दृष्ट स्तरों वाली जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a
separate compilation

वाणिज्य मंत्रालय

(आयात व्यापार नियंत्रण)

सार्वजनिक सूचना सं. 39-आईपीसी (पीएन)/84

नई दिल्ली, 1 अगस्त, 1984

विषय: 1983-84 के लिए 20 मिलियन येन की जापानी अनुदान सहायता के अन्तर्गत भारत के राष्ट्रीय अभियानार्थ नई दिल्ली द्वारा जापान से भारत के पत्तनों पर उपस्कर्ताओं को जाने के लिए आवश्यक भाष्ट्रोफिल्म उपस्कर्ताओं और सेवाओं के आयात के लिए लाइसेंस दाताएँ

मिस्सिस लॉ. आईपीसी/23(4)/84—भारत के राष्ट्रीय अभियानार्थ, नई दिल्ली द्वारा जापान से 20 मिलियन येन की जापानी अनुदान सहायता के अन्तर्गत माइक्रोफिल्म उपस्कर्ताओं के आयातों के लिए लागू होने वाली जैसी शर्तें इस सार्वजनिक सूचना के परिणाम में दी गई हैं, उन्हें जानकारी के लिए अधिसूचित किया जाता है

प्रकाश घन्द जैन, मुख्य नियंत्रक, आयात एवं नियंत्रि

वाणिज्य मंत्रालय, सार्वजनिक सूचना सं. 39-आईपीसी (पीएन)/84 दिनांक 1 अगस्त, 1984 का परिणाम

1983-84 के लिए 20 मिलियन (येन 20,000,000) येन की जापानी अनुदान सहायता के अन्तर्गत जापान से भारत में माइक्रोफिल्म उपस्कर्ता और उन्हें भारत में पत्तनों तक उपस्कर के आयात के लिए आवश्यक सेवाओं के आयात के लिए साइरेंस दाताएँ

खण्ड-1 सामान्य शर्तें

(1) 1983-84 के लिए 20 मिलियन येन (लागत एवं भाड़ा) की जापानी अनुदान सहायता का उपयोग माइक्रोफिल्म उपस्कर और उन्हें भारत में पत्तनों तक ले जाने के लिए आवश्यक सेवाओं के आयात के लिए जापानी संस्थानों को भूतानत के लिए भारतीय राष्ट्रीय अभियानार्थ, नई दिल्ली द्वारा किया जाएगा।

(2) आयातक के नाम में कूल येन 22 मिलियन (लागत दोभाड़ा) की घन्दराणि तक के लिए आयात लाइसेंस जारी किए जाने चाहिए और इस पर “1983-84 के लिए येन 20 मिलियन जापानी अनुदान सहायता” अभिलेख अंकित होता चाहिए। प्रथम और द्वितीय प्रत्यय के लिए लाइसेंस कोड “एस/जेएन” होता।

1(3) आयात लाइंसेस के मद्दे विदेशी मुद्रा का प्रेषण अनुमेय भर्ती होगा किंतु बैंक आंक इंडिया टोकियो को जो प्रभार सामान्य बैंकिंग प्रणाली के माध्यम से प्रेषित किए जाते हैं, वे इसमें शामिल नहीं हैं। यदि कोई हो तो, भारतीय एंजेंट को कमीशन का भुगतान भारतीय रुपए में किया जाना चाहिए, लेकिन ऐसे भुगतान लाइंसेस मूल्य का ही एक अंग समझे जाएंगे और अस्ति लाइंसेसधारी भी तीन बालू किए जाएंगे।

1(4) इस अनुदान सहायता के असरांश उपस्कर केवल जापान से ही अधिकार प्राप्त किए जाने चाहिए।

1(5) आयात लाइंसेस लागत-भीमा-भाड़ा के आधार पर जारी किए जाएंगे, जिनकी वैधता 31-3-1985 तक होगी।

1(6) संविदा में भुगतान की व्यवस्था नकद आधार अधारांश बैंक आंक इंडिया, टोकियो को जापानी संभरकों द्वारा लदान दस्तावेजों के प्रस्तुत करने पर करनी चाहिए। विवरण की अवधि निम्न प्रकार से होनी चाहिए :

"विवरण 15-3-1985 तक पूर्ण हो जाना चाहिए।"

1(7) संविदा का मूल्य (केवल लागत एवं भाड़े के आधार पर) येन में (येन का अंश हटा देना चाहिए) प्रदर्शित किया जाना चाहिए और यदि कोई हो तो, भारतीय अधिकारी का कमीशन निकाल देना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में भारतीय अधिकारी का मूल्य, किसी अन्य मुद्रा में प्रदर्शित नहीं किया जाना चाहिए।

जहाज पर्यावरण नियन्त्रण शुल्क लागत एवं भाड़ा राशि भलग से दर्शाई जानी चाहिए, किन्तु संविदा में यह स्वतः स्पष्ट होना चाहिए कि भाड़े का भुगतान यातायिक आधार पर किया जायगा भलग उसमें वर्णिया गया भाड़ा आस्तविक बचतों के प्रतिरिक्त भुगतान की राशि होगा।

1(8) कम संविदा जापानी राष्ट्रियों द्वारा नियंत्रित, केवल जापानी राष्ट्रियों या जापानी व्यापिक व्यक्तियों द्वारा की जानी चाहिए।

खंड-2 संभरण टेकों में निम्नलिखित प्राप्तधान रुप से भ्रमणित होना चाहिए :—

2(1) टेको की व्यवस्था 1983-84 के लिए येन 20 मिलियन के अनुदान सहायता के अनुसार भारत और जापान की सरकारों के बीच हुए 11 मई, 1984 को हुए समझौते के अनुसार होमी चाहिए और योनों सरकारों के अनुमोदन के प्रधोन होगी।

2(2) संभरकों को भुगतान "भुगतान के प्राप्तिकार" (एपी) के माध्यम से किए जाएंगे। जो 1983-84 के लिए जापान अनुदान सहायता के अंतर्गत बैंक आंक इंडिया, टोकियो के लिए सहायता लेखा एवं लेखा परीक्षा नियंत्रक, विस मंत्रालय, आधिकारिक कार्य विभाग, यू० सी० ओ० बैंक विलिंग, संसद मार्ग, नई विल्ली-110001 को देगा जो कि जापानी संभरकों को भुगतान करने के लिए बैंक आंक इंडिया, टोकियो को अनुबंध-2 के अनुसार एक "भुगतान प्राप्तिकार-पत्र" (एपी) जारी करेगी। प्राप्तिकार-पत्र (एपी) की प्रतियां भारत का दूतावास, टोकियो, आयातक आधार के बैंक और किंतु मंत्रालय, आधिकारिक कार्य विभाग के जापान अनुभाग को भेजी जाएंगी।

2(3) जापानी संभरक पौत्री सूचनाओं एवं दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के लिए सहमत होने एक और भारत सरकार एवं दूसरी और जापान सरकार द्वारा अपेक्षित होंगे।

2(4) जापानी संभरक भारतीय दूतावास, टोकियो, के परामर्श पर पौत्र परिवहन व्यवस्था करने के लिए सहमत है और इस उद्देश्य के लिए वह भारतीय दूतावास, टोकियो को शामिल माल की सुपुर्दी के कार्यक्रम से अवगत करायेगा और पौत्र-निधान से कम से कम ४० सप्ताह पूर्वे भारतीय दूतावास को सूचना देगा जिससे कि उचित व्यवस्था हो सके। विशेष मामलों में जहां आयातक इच्छुक हों, सूचना की इस अवधि को कम किया जा सकता है। जापानी संभरक को प्रत्येक पौत्र-निधान के परामर्श आवश्यक व्यापर देते हुए, तार से सूचना भेजने के लिए सहमत होना चाहिए और उसकी एक प्रति भारतीय दूतावास, टोकियो को भेजी जानी चाहिए।

खंड-3 भारत और जापान का सरकारी द्वारा डेके का अनुमोदन

3(1) ऐसे ही आदेशों को अन्तिम रूप से लिए जाते हैं, लाइंसेसधारी को दोनों पारियों द्वारा विधिवत् इस्तेवारित डेके की चार प्रतिशत जापानी संभरकों को भारतीय आयातक द्वारा दिए गए कम अवधि के साथ जापानी संभरकों द्वारा लिखित रूप में पुस्तिकान्न आदेश की ओर प्रतियां या सभी प्रकार के पूर्ण आयात लाइंसेस की दो फोटो प्रतिशतों के साथ अनुबंध-1 के प्रपत्र के "(एपी) जारी करने के अंदेश" की दो फोटो प्रतियां अवर युनियन (टी.ए.) आधिकारिक कार्य विभाग, विस मंत्रालय, नार्थ ब्लाक, नई विल्ली को भेजनी चाहिए। उपर्युक्त प्रक्रिया संविदा की विधय-अस्तु या उसकी कीमत के अवश्यक आशोदनों से उत्तम सभी संविदा संरक्षणों के लिए यही लागू होती।

3(2) विस मंत्रालय (डीईए) जापान अनुभाग 1983-84 के लिए 20 मिलियन देन की जापानी अनुदान सहायता के जीवीन वित्तान देने के लिए संविदा की एक प्रति जापान सरकार के अनुमोदन के लिए भेजेगा, और इसी के साथ-साथ उपर्युक्त (1) में उल्लिखित दस्तावेजों का एक सैद्ध सहायता लेखा व लेखा प्रतीक्षा नियंत्रक और भारत के दूतावास, टोकियो को भी भेजेगा।

3(3) जापान भरतार ने ठेका अनुमोदन प्राप्त करने के बाद वित्त मंत्रालय आधिकारिक विभाग, नार्थ ब्लाक की उनकी सूचना सहायता लेखा व लेखा परीक्षा नियंत्रक, आधिकारिक कार्य विभाग, विस मंत्रालय, यू० सी० ओ० बैंक विलिंग, संसद मार्ग, नई विल्ली-110001 को देगा जो कि जापानी संभरकों को भुगतान करने के लिए बैंक आंक इंडिया, टोकियो को अनुबंध-2 के अनुसार एक "भुगतान प्राप्तिकार-पत्र" (एपी) जारी करेगी। प्राप्तिकार-पत्र (एपी) की प्रतियां भारत का दूतावास, टोकियो, आयातक भारत में आयातक के बैंक और किंतु मंत्रालय, आधिकारिक कार्य विभाग के जापान अनुभाग को भेजी जाएंगी।

3(4) भुगतान के लिए प्राप्तिकार-पत्र (एपी) की प्राप्ति के बाद बैंक आंक इंडिया, टोकियो, जापान सरकार, भारत का दूतावास टोकियो, भारत में आयातक के बैंक और सहायता लेखा एवं लेखा परीक्षा नियंत्रक को सूचना देते हुए इस प्राप्ति की सूचना से जापानी संभरक की अवगत कराएगा।

3(5) पोतलदान करने के बाद जापानी संभरक अपने बैंकरों के माध्यम से एपी में उल्लिखित दस्तावेज बैंक आंक इंडिया, टोकियो को प्रस्तुत करेगा। यदि दस्तावेज सही पाए गए तो बैंक आंक इंडिया, टोकियो दस्तावेजों में उल्लिखित धनराशि को जापानी संभरकों को अपने बैंकरों के माध्यम से निहा कराएगा।

3(6) जापानी संभरकों को भुगतान की व्यवस्था करने के लिए बैंक आंक इंडिया, टोकियो की देय बैंक व्हर्च भारत सरकार के लेखों को प्रभावित किए जिनका सामान्य बैंक प्रणाली के माध्यम से भारत में आयातक से संबद्ध बैंक द्वारा बैंक आंक इंडिया टोकियो को ब्रान परेयित करके निर्णीत किया जाएगा।

खंड-4 जापा कराने का उत्तरदायित्व

4(1) मूल विनियम पौत्र-परिवहन दस्तावेज नियंत्रित द्वारा से बैंक आंक इंडिया टोकियो द्वारा भारत में आयातक के संबद्ध बैंक को भेजे जाएंगे जो भारतीय स्टेट बैंक या किसी भी राष्ट्रीय लैन बैंक जो अनुबंध-1 के (ग) में उल्लिखित है, की शाखा होती, उस बैंक को दस्तावेजों के ये विनियम सेट केवल इस वाल का सुनियंत्रित कर लेने के बाद ही संबद्ध आयातक को देने चाहिए कि जापानी संभरकों को चुकाई गई यह धनराशि के बायावर दूधा जामा करने में जहां देय योग्य है व्याज के व्हर्च सहित जापानी संभरकों को भुगतान कर दिया जाया है और इस धनराशि पर जापानी संभरकों को बैंक आंक इंडिया, टोकियो द्वारा किए गए भुगतान की तिथि से बास्तविक रूप से जमा करने की तिथि की अवधि पर पहले 30 दिनों के लिए 12% प्रतिवर्ष की दर से शेष अवधि के लिए 18 प्रतिवर्ष प्रति वर्ष की

कर से हिराव लगा कर व्याज सार्वजनिक सूचना सं० 31 आईटीसी (पी एन)/83 दिनांक 10-3-83 के अनुसार सरकारी लेखे में जमा कर दिया गया है। व्याज दोनों दिनों अधिकृत जिस यिन जापानी संभरक को भुगतान दिया जाता है, और जिस दिन सरकारी लेखे में रुपया जमा किया जाता है, के लिए देय है देखिए सार्व० सूचना सं० 103-आईटीसी (पी एन)/76, दिनांक 12-10-1976 द्वारा संगीतन सार्वजनिक सूचना सं० 74-आईटीसी (पी एन)/71 दिनांक 31-5-1974 ।

येन भुगतान के समस्त रुपए की गणना करने के लिए अपनाई गई मुद्रा विनियम की दर मुक्य परिवर्तन, आयात-नियांत्रित की सार्वजनिक सूचना सं० 8-आईटीसी (पी एन)/76, दिनांक 17-1-76 में यथा निर्धारित मुद्रा विनियम की प्रतिवित मिश्रित दर या समय-समय पर मुक्य नियंत्रक, आयात-नियांत्रित की सार्वजनिक सूचनाओं वा भास्त्रों द्विर्ज बैंक के मुद्रा विनियम नियंत्रण परिवर्तनों के माध्यम से सरकार द्वारा अधिसूचित दर होती है। इस संबंध में और व्याज की दर के संबंध में भी कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। इस संबंध में और व्याज की दर के संबंध में भी कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। आयातक को यह भी सुनिश्चय करना चाहिए कि अपने बैंकरों से दस्तावेज लेने के पश्चै देय धनराशि सरकारी लेखे में सही रूप से जमा करा दी गई है।

वह सुनिश्चय करने की आयातक की जिम्मेदारी होती कि देय धनराशि सरकारी लेखे में ठीक से जमा करता ही गई है जबकि उल्लेखित विशेष परिस्थितियों में सीमा-शुल्क प्राधिकारियों से माल की सुपुर्दी प्राप्त की हो। उस माल में जब आयातक सरकार को देय धनराशि, माल छुपवाते से पूर्व जमा करवाने में अमरमध्य होता है तो उसे आगे पृल०८०८० जारी करता रोक दिया जाएगा और मुक्य नियंत्रक, आयात-नियांत्रित को तथ्यों से अवगत करवाया जाएगा जिसे ऐसे आयातक को आगे कोई धायत लाइसेंस न जारी किया जाए।

लेखा शीर्ष यिसमें उपर्युक्त रूपया निषेप किया जाएगा वह है “के-टिपोजिट्स एंड एडवॉसिज-८४३-मिविल डिपोजिट्स-डिपोजिट्स फार वर्चेजिज एट्सेट्रा एग्राइ-परवेजिज ब्रंडर ग्रांट एंड फ्राम वि गवर्नमेंट आफ जापान फार १९८३-८-४ भारत में ऐतिहासिक टिक्काओं के संरक्षण के लिए भाइकोफिल्म उपलब्धसेवाओं की शरीद के लिए अनुदान।

4(2) ऊपर उल्लिखित धनराशि या तो भारतीय रिजर्व बैंक, नहीं विल्सो में जालान के बाहिने कोने में कोड सं० 5130000009 दर्शने हुए या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तीस हजारी, विल्सो में या यदि संभव न हो तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तीस हजारी शाखा, विल्सो-६ (आदेशी और प्राप्त) के नाम और उसको देय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या इसकी सहायक शाखा या किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक (आवेशक) से प्राप्त डिमॉड श्रावट के माध्यम से सरकार के लाले में सकद जमा करानी चाहिए। सार्वजनिक सूचना सं० 184-आईटीसी (पीएन)/68, दिनांक 30-३-1968, सं० 233-आईटीसी (पीएन)/68, दिनांक 24-10-68 और सं० 132-आईटीसी (पी एन)/71, दिनांक 5-10-71, सं० 74 आईटीसी (पी एन)/74, दिनांक 31-5-1974 और सं० 103-आईटीसी (पी एन)/76, दिनांक 12-10-1976 में दृष्ट्य है।

4(3) भारत में संबद्ध बैंक भी उपर्युक्त निर्धारित विधि के अनुसार ऐसे अतिरिक्त निषेप भेजेगा और जैसे ही सेवा प्रमाण के लिए सरकार द्वारा इसकी मांग की जाती है तो इस प्रकार की गई मांग के बाद सात दिनों के भोत्र निषेप करेगा।

चालान के विभिन्न कालम भरते समय आयातकों/उमके बैंकरों को यह सुनिश्चित कर देना चाहिए कि सार्वजनिक सूचना सं० 132-आईटीसी (पीएन)/71, दिनांक 5-10-71 और सार्वजनिक सूचना सं० 103-आईटीसी (पी एन)/76 दिनांक 12-10-76 के साथ की जाने वाली सार्वजनिक

सूचना सं० 74-आईटीसी (पी एन)/74 दिनांक 31-5-1974 के पृष्ठ-२ में निर्धारित सूचना चालान के “धन परेषण और प्राधिकारी (यदि कोई हो) के पूर्ण व्यापे” कालम में निरपवाद रूप से निर्दिष्ट किए गए हैं। यज्ञाना भासान में निम्नलिखित और निरपवाद रूप से प्रस्तुत करने चाहिए।

(क) विव मंदालय के “ए पी” (भुगतान के लिए प्राधिकार पद) की सं० एं द्वारा

(ख) येन मुद्रा की वह धनराशि यिसके संबंध में अपनाई गई परिवर्तन की दर को मात्र निषेप किए जाते हैं।

(ग) जापानी संभरक को भुगतान की तिथि।

(घ) भुगतान किए गए व्याज की धनराशि और वह जब्ति यिसके लिए इसकी गणना की गई है।

(इ) निषेप की गई कुल धनराशि

(व्याज की गणना जापानी संभरक को भुगतान की तिथि से सरकारी लेखे में तुल्य रूपया जमा करने की तिथि तक करनी है।

उसके पश्चात् सी ए एंड/ए द्वारा जारी किए गए ए/पी (भुगतान के लिए प्राधिकारीपद) का संवर्म देते हुए और बीजक सथा पोत परिवहन वस्तावेजों को संलग्न करने हुए यज्ञाना चालान, रूपया जमा करने का साध्य ऐसे हुए पंजीकृत डाक द्वारा सी ए एंड ए को मेजा जाना चाहिए।

टिप्पणी: भारत में आयातक के बैंकों को यह सुनिश्चित कर देना चाहिए कि बैंक ऑफ इंडिया टोकियो से भुगतान की सूचना और विनियम पोत परिवहन वस्तावेजों को प्राप्ति के 10 दिनों के भीतर रूपया निरपवाद रूप से जमा कर दिया गया है और यह कि इसके सुरक्ष व्यापक इसकी सूचना सी ए एंड ए विव मंदालय (प्रार्थिक कार्य विभाग) नई विली को दे दी गई है।

4(4) भारत में संबद्ध भारतीय बैंक को लाइसेंस की मुद्रा विनियम नियंत्रण प्रति पर रूपया निषेपों की धनराशि का पृष्ठांकन करना चाहिए और अपेक्षित “एस” प्रश्न भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बंडी को भेजना चाहिए।

चाहू-५ विविध व्यवस्थाएं

5(1) अनुदान सहायता के उपयोग पर रिपोर्ट

लायातक को पोतलदान और उसके भ्रष्टीन किए गए भुगतान और विशेष धनराशि के बारे में ए/पी जारी हो जाने के पश्चात् एक मासिक रिपोर्ट सहायता लेखा एवं लेखा परीक्षा नियंत्रक, प्रार्थिक कार्य विभाग, यू. सी. प्रा. बैंक विलिंग, संसदि मार्ग, नई विली को भेजनी चाहिए।

5(2) आयातक को इस अनुदान सहायता के अधीन मर्दों के आयात को संबंध में उन विशेष प्रावधानों से संभरक को अवगत करा देना चाहिए जो माल के लेन-देन में संभरक पर प्रभाव डालती है।

5(3) विवाद

यह समझ लेना चाहिए कि लायातकों और संभरकों के बीच यदि कोई विवाद उठेगा तो उसके लिए भारत सरकार कोई उत्तर-शायित्व नहीं लेनी। बैंक ऑफ इंडिया, टोकियो द्वारा भुगतान से पहले संभरक द्वारा पूरी की जाने वाली शते आयातक द्वारा अनुबंध-१ में “भुगतान की शती” के प्रतीक्षण गठिये तरह से स्पष्ट करनी चाहिए। संविदा की शती में विवाद निपटाने से संबंधित व्यवस्थाएं शामिल होनी चाहिए।

5(4) भविष्य अनुदेश

जापान से 1983-84 के लिए अनुदान सहायता के अधीन आयातों से उपर्युक्त या उनके संबंध में खड़े होने वाले किसी भी मालके या सभी मा-

के संबंध में समय-समय पर भारत सरकार द्वारा जारी किए गए निदेशों, अनुदेशों या आदेशों को और सभी दायित्वों को आयातक को तुरन्त पूरा करना होगा।

5(5) अतिक्रमण या उल्लंघन

उपर्युक्त अनुच्छेदों में निवारित की गई शर्तों के अतिक्रमण या उल्लंघन करने पर आयात-नियम (नियंत्रण) अधिनियम के अधीन उचित कार्रवाई की जाएगी।

5(6) अनुबंधों की गूची

अनुबंध-1	ए/पी जारी करने के लिए प्रारंभना-पत्र
अनुबंध-2	ए/पी का प्रयत्न

अनुबंध-1

“भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र जारी करने के लिए प्रारंभना पत्र”

सं०

दिनांक

सेवा में,

सहायता सेवा एवं सेवा परीक्षा नियंत्रक,
विस मंत्रालय,
आधिक कार्य विभाग,
श्रू सी ओ बैंक बिल्डिंग, प्रथम मंजिल,
संसद मार्ग, यौवन दिल्ली-110001

अनुबंध-2

विषय: 1983-84 के लिए येन 20 मिलियन की जापान अनुदान सहायता के प्रत्यर्पत्त जापान से भारत में पत्तमों के लिए उपस्कर के यातायात के लिए आवश्यक माइक्रोफिल्म उपस्कर और सेवाओं का आयात।

महोदय

ऊपर उल्लिखित अनुदान सहायता के अधीन जापान से उपर्युक्त के आयात के संबंध में हम आपको निम्नलिखित और भेजते हैं जिससे कि आप संबूद्ध जापानी संभरक के पत्र में वैक और इंडिया, टोकियो की भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र (ए/पी) जारी कर सकें:—

- (क) भारतीय आयातक का नाम और पता
- (ख) आयात लाइसेंस की संख्या, दिनांक और मूल्य और वह तिथि जब तक यह वैध है।
- (ग) अधिप्राप्ति के तरीके—क्या यह प्रत्यक्ष खरीद पर आधारित है या सीमित खुली निविवा पर आधारित है। इस नामले में कारणों सहित यह निर्दिष्ट करना है कि क्या निविवा का निर्णय उपर्युक्त तकनीकी प्रस्ताव के आधार पर किया गया है।
- (घ) माल का संक्षिप्त विवरण
- (ङ) माल का उद्गम देश
- (च) संविदा की कुल लागत और भाड़ा मूल्य (येन में)
- (छ) यदि कोई ही सो भारतीय रुपए में भारतीय एंजेंट के कमीशन की घनराणि (येन में)
- (ज) वह कुल लागत तथा भाड़ा मूल्य (येन में) जिसके लिए भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र की आवश्यकता है।
- (झ) जापानी संभरकों के साथ की गई संविदा का नाम और दिनांक
- (झ) जापानी संभरक का नाम और पता और एक पात्रता-प्रमाण-पत्र (यो प्रतियों में संलग्न करें)

(ट) वे भुगतान शर्तें और संभावित नियंत्रित जिनको संविदा प्रत्यर्पत्त भुगतान देय होंगी।

(ड) माल को सुपुर्दों पूर्ण करने की प्रस्तावित तिथियाँ

(इ) यैक और इंडिया टोकियो को भुगतान करते समय प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज़ (प्रस्तेक सैट फी संख्या और उनका निपटा न दर्शाते हुए)

(इ) पोतलदान अनुदेश (अनुमेय या और अनुमेय आहनान्तरण/आंशिक पोतलदान निर्दिष्ट कोणिएं)

(ज) भारत में आयातक बैंक का नाम और पता।

(क) आयातक द्वारा बचनबद्धता:—“हम एतद्वारा बचन देते हैं कि हम विदेशी संभरक को वेय धनराणि के समतुल्य रूपए की पूर्ण धनराणि को सरकार द्वारा निवारित कियागिथि से और प्रत्यनित दर पर सही रूप से जमा करवा देंगे। माल (आयातित सामग्री) के प्रत्येक परेण्य की सुपुर्दों प्राप्त करने से पूर्व राणि योग्य ही जमा करवा दी जाएगी। विदेशी राणियों की सेवाओं के लिए भुगतान के मामले में जैसे ही हमारे द्वारा विदेशी संभरक के संगत बीजक अनुमोदित किए जाते हैं और संभरक को भुगतान किया जाता है ऐसे ही राणि जमा करवा दी जाएगी।”

सं० एक

भारत सरकार

विस मंत्रालय

(आधिक कार्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक

सेवा में,

बैंक और इंडिया,

टोकियो शास्त्रा,

टोकियो (जापान)

विषय:— 1983-84 के लिए येन 20 मिलियन की जापान अनुदान सहायता के अन्तर्पत्त जापान से भारत में पत्तमों को उपस्कर के यातायात के लिए माइक्रोफिल्म उपस्कर और सेवाओं का आयात/भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र जारी करना।

प्रिय महोदय,

आपके बैंक के साथ को किए गए समझौते की शर्तों के अनुसार आपको एनद्रवारा परिषिष्ट में विए गए यथा संलग्न व्यारे के अनुसार मध्यश्री को येन धनराणि के भुगतान के लिए प्राधिकृत किया जाता है।

2. कृपया भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र (ए/पी) की पावती के आरे में संभरकों को सूचना दें और इसकी प्रत्येक सूचना पत्र की एक प्रति जापान सरकार, आयातक बैंक, भारत के राजदूतावास, टोकियो और इस मंत्रालय को पृष्ठाकृत की जाए।

3. भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र की शर्तों के अनुसार भुगतान परिषिष्ट में यथा संकेतित लदान दस्तावेजों के आधार पर किया जाएगा।

4. आयातक द्वारा आपको दस्तावेज संभरकों एवं बैंकरों के प्रभार को भेजने आदि के लिए माड़े सहित अदा किए जाने वाले बैंकिंग भाड़े आयातक के बैंक द्वारा भीष्य ही निर्धारित किए जाएंगे।

5. जैसे ही जापानी संभरक द्वारा प्रस्तुत किए गए लदान वस्त्रोंवें आदि के आधार पर आपके द्वारा कोई भी भुगतान किया जाता है तो इसकी मूल्याना निर्धारित प्रपद्म में इस पंचालय और आयातक के द्वैक कों और जानी चाहिए ।

6. इस मंस्तानी की विशेष अनुमति के बिना मूलाना के लिए प्राविकार पत्र के लिए कोई भी संशोधन जारी नहीं किया जा सकता है।

७. यह भूगतान प्राधिकार पत्र तक वैध रहेगा ।

भवदीय.

(लेखा अधिकारी)

1. आयातक को उमके पत्र सं० विनांक के संदर्भ में ।

उमसे अनुरोध किया जाता है कि वे ईकरों के परशाम्प दस्तावेजों का सुपुर्द्दगी लेमे से पूर्ख अपने ईकरों के भाष्यम्-रो रसायन निशेष आदि और जमा करवाने की व्यवस्था करें। यदि विणेप करित्यितयों की वजह से मूल परिवहन दस्तावेज अस्तुत किए जिमा भीमा-भूलक प्राधिकारियों और पलान के प्राधिकारियों से माल की सुपुर्द्दगी सीधे ही प्राप्त करनी ही तो यहां सुपुर्द्दगी प्राप्त करने से पूर्ख धनराशि जमा करवानी आहिए। विदेशी संभरकों द्वारा दी गई सेवाओं के लिए भूगतान के भारती में जैसे ही भूगतान के लिए ओजिक अनुमोदित किए जाते हैं वैसे ही धनराशि जमा करवा देना आहिए। शीघ्र ही और सही रूप से धनराशि जमा करवाने में असमर्थ होने पर लाल्होंसग प्रार्थों में उल्लिखित कारंबाई की जाएगी।

2. आपातक का वैकं.....उसे विवेदन किया जाता है कि भारतीय बैंग आफ इंडिया, टोकियो, ब्रावो से दस्तावेज प्राप्त करने पर जापानी संभरकों को ये भुगतान के बराबर देपए जमा करने की व्यवस्था करें। संभरकों को चुकायी गई धनराशि के बराबर देपए को गणना सार्वजनिक सूचना सं० ३-आईटीसी (पीएम) /२६, दिनांक १७-१-७६ गा अन्य ऐसी सार्वजनिक सूचना जो राष्ट्रमय पर जारी की जाएँ के अनुमार विवेदन संभरकों को भुगतान करने वी तिथि को यथा प्रचलित पन्दित वर्तन की मिश्रित दर पर की जाएगी। विवेदी संभरक के भुगतान अदानगी करने की तिथि तक संभरकार के लेखे में मूला रूपया जमा करने की अपवाह के लिए सार्वजनिक सूचना सं० ३१ आईटीसी (पीएम) /८३ दिनांक १०-८-८३ के अनुमार पहले ३० दिनों के लिए १२ प्रतिशत दर पर और इससे अधिक की गणना की गई अवधि के लिए १८ प्रतिशत की दर से व्याज भी सरकारी लेखे में जमा करना होगा। व्याज दोनों दिनों के लिए देव होगा अर्थात् वह तिथि भी जिस दिन सरकारी संभरक को भुगतान किया जाता है और वह तिथि भी जिस दिन सरकारी लेखे में रूपया निक्षेप किया जाता है। (यदि इस दर में कोई पर्यावरतन होता तो इसकी सूचना तुरन्त दी जाएगी)। यह सुनिश्चय कर लेना चाहिए कि आगतक को सीमान्शुलक भिकासी के लिए आगाम दस्तावेजों का मूल सेट हिं जाने में पूर्व यह धनराशि जमा कराई जाती है।

ये भ्रमरशियां या सो यासान के बाहिने कोने में कोड नं० 5130000009 को दर्शाते हुए रिजर्व बैंक आफ ईडिया, नई दिल्ली या स्टेट बैंक आफ ईडिया तीन दृजाएँ, दिल्ली में जमा करनी चाहिए या स्टेट बैंक आफ ईडिया की किसी शाखा या इमारों अनुपरी संस्थाओं या किसी भी राज्यीयकृत बैंक से उनके द्वारा प्राप्त की गई स्टेट बैंक आफ ईडिया, तीस दृजाएँ शाखा, दिल्ली-6 (आदिगां और अग्रना) के नाम में और उसकी देव वर्णीय हृष्टों के माल्यम में करनी चाहिए। इस संबंध में अतिका ध्यान सार्वजनिक सुधना सं० 233-आर्टीसी (पीएन)/६८, दिनांक ५-१०-६८, सं० 132-आर्टीसी (पीएन)/७१, दिनांक ५-१०-७१, सं० ७४-आर्टीसी (पीएन)/७४, दिनांक ३१-५-७४ ओर सं० 103-आर्टीसी (पीएन)/७६, दिनांक १२-१०-७६ की जरूरी की ओर यिसाया जाता है। लेकिन पीछे जिसमें धरतराशि जमा की जाएगी तब "के डिरीकिटुन एन पट्टासितिव ४४३

सिविल हिपोजिट्स—हिपोजिट्स फार परवेजिस एटसेक्ट्रा एड्राइ—परवेजिस ग्राउंड एंड फ्राम दि गवर्नमेंट आफ जापान कार 1983-84 है और विस्तृत लेख गोपीक” “भारत में मिट्टिकार्गिक रिकार्डों के संरक्षण के लिए माइक्रोफिल्म उपस्थित की खारीब के लिए ये ने 20 मिलियन की अनदान सहायता”।

जिन मामलों में सुन्ध शपथा रिक्वेट थें कि आफ इंडिया, नई दिल्ली या स्टेट बैंक आफ हैंडिया, तीस हजारी में सार्वजनिक सूचना सं० 132-आई-टे सी (पीएन) / 71, दिनांक 5-10-71 के अनुसार नकद जमा किया जाता है उनमें जातानां को मूल रूप में एक प्रतिलिपि थें कि आफ इंडिया, टोकियो शाखा से प्राप्त सूचना टिप्पणी का पूर्ण विवरण देते हुए अप्रेसण पत्र गम्भिन उनके निम्नलिखित पते पर भेजी आएगी :—

सहायता लेखा तथा लेखा परीक्षा नियंत्रक,

वित्त मंत्रालय (आयिक कार्य विभाग)

पहली मंजिल, यू सी औ बैंक बिल्डिंग,

संसद मार्ग, सद दिल्ली-110001

जिस मामले में तुल्य रूपया ऊपर संकेतित सार्वजनिक सूचना विनांक 24-10-68 में यथा उल्लिखित दर्शानी हुई द्वारा प्रेपित करना है उमसकी सूचना उपर्युक्त पते पर भेजी जानी चाहिए। सभी मामलों में व्याज की चुकावाई गई धनराशि और जिस अवधि के लिए व्याज की गणना की गई है और उसके साथ जमा किए गए तुल्य रूपए का पूरा ध्येय इस विभाग को भेजना चाहिए।

समझपार, संभरक के बैकर के खंचों सहित यांच कोई हो तो, बैकिंग खंचों और बैक आफ दिया, टोकियो आंच के अन्य खंचे दियियन बैक आफ हूंडिया, टोकियो शाखा हारा सीधे ही निश्चारित किए जाएंग ।

4. मार्गीय दग्धवास, टोकियो

५. अधर सचिव (टीए) शाखा, वित्त मंत्रालय, भार्तीय कार्य विभाग, नई दिल्ली।

सेखाधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE
IMPORT TRADE CONTROL
PUBLIC NOTICE NO. 39-ITC (PN) 84

New Delhi, The 1st August, 1984

Subject.—Licensing conditions for import of Microfilm equipment and services necessary for transportation of the equipment to ports in India from Japan by the National Archives of India, New Delhi under Japanese Grant Aid for 1983-84 of Yen twenty million.

File No. IPC/23(4)/84—The terms and conditions governing imports under the Japanese Grant Aid of yen 20 million of Microfilm equipment from Japan by National Archives of India, New Delhi, as given in Appendix to this Public Notice are notified for information.

P.C. JAIN, Chief Controller of Imports & Exports

Appendix to Ministry of Commerce Public Notice No. 39-ITC (PN)84 dated the 1st August 1984

Licensing Conditions for import of microfilm equipment and services necessary for the transportation of the equipment to ports in India from Japan under Japanese Grant Aid for 1983-84 of Yen twenty million (Yen 20,000,000).

Section I General Conditions

I (i) The Japanese Grant Aid for 1983-84 of Yen 20 million (C&F) is intended to be used for financing payments to Japanese Suppliers for import of microfilm equipment and services necessary for the transportation thereof to ports in India, by the National Archives of India, New Delhi.

I (ii) The import licence should be issued for an amount no exceeding yen 22 million (CIF) in favour of the importer, and should bear the superscription "Yen 20 million Japanese Grant Aid for 1983-84". The licence code for the first and second suffix will be "S|JN".

I (iii) No remittance of foreign exchange will be permitted against the import licence, except bank charges to the Bank of India, Tokyo which may be remitted through normal banking channels. Payment towards Indian Agent's Commission, if any, should be made in Indian rupees to the agents in India. Such payments, however, will form part of the licence value and will, therefore, be charged to the licence.

I (iv) The equipment should be procured only from Japan under this Grant Aid.

I (v) The import licence will be issued on CIF basis with validity upto 31-3-85.

I (vi) The contract should provide for payment on cash basis i.e. on presentation of shipping documents by the Japanese suppliers to the Bank of India, Tokyo. It should also provide for the period of delivery as follows :—

"delivery to be completed by 15-3-1985".

I (vii) The contract value (C&F basis only) should be expressed in Yen (fraction of Yen should be omitted) and should exclude Indian Agent's Commission, if any. In no circumstances the contract value should be expressed in any other currency.

The FOB cost and freight amount should be shown separately but it should be clarified in the contract itself whether the freight will be payable on actual basis or whether the freight charges indicated therein would be the amount payable irrespective of the actual charges.

I (viii) The purchase contract should be entered into only with the Japanese nationals or Japanese juridical person controlled by Japanese nationals.

SECTION II

The following provision should be specifically incorporated in the supply contract :—

II (i) The contract is arranged in accordance with the Agreement dated the 11th May, 1984 between the Government of India and Government of Japan concerning the Grant Aid of Yen 20 million for 1983-84 and will be subject to the approval of both the Governments.

II (ii) Payments to the suppliers shall be made through an 'Authorization to pay' (A|P) which will be issued by the Controller of Aid Accounts & Audit, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, UCO Bank Building, Parliament Street, New Delhi-110001 in favour of the Bank of India, Tokyo, under the Japanese Grant Aid for 1983-84.

II (iii) The Japanese suppliers agree to furnish such information and documents as may be required by the Government of India on the one hand and the Government of Japan on the other.

II (iv) The Japanese supplier agree to make shipping arrangements in consultation with the Embassy of India, Tokyo and that for this purpose he would keep the Embassy of India, Tokyo informed of the delivery schedule of the goods involved and notify the Embassy of India, at least six weeks in advance of the shipping required so that suitable arrangements should be made. In exceptional cases, where the importer require it this period of notice may be reduced. The Japanese supplier should also agree to send a cable advice to the importer after each shipment giving the necessary details and a copy thereof should be sent to the Embassy of India, Tokyo.

Section III : Contract Approval by Governments of India and Japan.

III (i) As soon as the orders are finalise, the importer should forward to the Under Secretary (I.A.), Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, North Block, New Delhi 4 copies of the contract duly signed by both parties or purchase orders by the Indian importer placed on the Japanese supplier supported by order confirmation in writing by the Japanese supplier or their photo copies complete in all respects together with two copies of the 'Request for issue of A|P' in the form at Annex. I. The above procedure will also apply to all contract amendments causing essential modifications to the contents of contracts or in its price.

III (ii) The Ministry of Finance (DEA) Japan Section will arrange to send one copy of the contract to the Government of Japan for their approval for financing under the Japanese Grant Aid for 1983-84 of en 20 million, and one set of the documents mentioned in (i) above will also be sent to the CAA&A and the Embassy of India in Tokyo simultaneously.

III (iii) On receipt of the contract approval from the Government of Japan, the Japan Section of the Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, North Block will inform the Controller of Aid Accounts & Audit, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance UCO Bank Building, Parliament Street, New Delhi-110001 of the same who will issue an 'Authorisation to Pay' (A|P) to the Bank of India, Tokyo in the form at Annexure II for

making payment to the Japanese supplier. Copies of the A/P will be endorsed to the Embassy of India, Tokyo, the importer, importer's Bank in India and Japan Section Department of Economic Affairs, Ministry of Finance.

III (iv) On receipt of the Authorisation to Pay (A/P) the Bank of India, Tokyo will intimate the fact of this receipt to the Japanese supplier under intimation to the Government of Japan, Embassy of India, Tokyo, the importers' Bank in India and the CAA&A.

III(v) The Japanese supplier shall, after effecting shipment present through his bankers the documents specified in the A/P to the BOI, Tokyo. If the documents are found to be in order, the Bank of India, Tokyo will release the amount specified in the documents to the Japanese supplier through his bankers.

III(vi) Banking charges payable to the Bank of India, Tokyo for arranging the payment to the Japanese supplier shall be settled by the concerned import's bank in India by remittances to the BOI, Tokyo through normal banking channel without affecting the Government of India's account.

Section IV : Responsibility for rupee deposit.

IV (i) The original negotiable shipping documents will be invariably forwarded by the Bank of India, Tokyo, to the concerned importers bank of India, which would be a branch of the State Bank of India or any of the nationalised banks as mentioned in (O) in Annexure-I who should release these negotiable set of documents to the importer concerned only after ensuring that the rupee equivalent of the Yen payments made to the Japanese supplier alongwith interest charges thereon calculated at the rate of 12 per cent per annum for the first thirty days and at 18 per cent for the period in excess thereof reckoned from the date of payment by the Bank of India, Tokyo to the Japanese Supplier to the date of actual rupee deposit, is deposited into Government of India account in terms of the Public Notice No. 31-ITC(PN)|83 dated 10-8-83. The interest is payable for both the days i.e. the day in which payment is made to the Japanese supplier and also the day on which rupee deposits is made in to Government account vide Public Notice No. 74-ITC(PN)|74 dated 31-5-1974 as modified under Public Notice No. 103-ITC(PN)|76 dated 12-10-1976. The exchange rate to be adopted for computing the rupee equivalent of the Yen Payment will be the prevailing composite rate of exchange as laid down in CCI&E Public Notice No. 8-ITC(PN)|76 dated 17-1-1976 or as may be notified by Government from time to time through Public Notices of the CCI&E or through Exchange control circulars of the Reserve Bank of India. Any change in this regard as also in regard to the rate of interest will be notified as and when necessary. It will be the responsibility of the Indian bank concerned to ensure that the amounts due are correctly deposited into Government Account before the import documents are handed over to the importers. The importer should also ensure that the amounts due are

correctly deposited into Government account before taking delivery of the documents from their bankers. It is the responsibility of the importer to ensure that the amounts due are correctly deposited in to the Government account promptly even when they obtain delivery of the goods from the customs authorities under exceptional circumstances. In case the importer fails to deposit the amounts due to Government before taking delivery of the goods, the issue of further IAS to him may be stopped and the matter reported to the CCI&E so that no further import license is issued to such an importer. The Head of Account to which the above rupee deposits should be credited is "K-Deposits and Advances-843-Civil Deposits-Deposits for purchases etc., abroad—purchase under Grant Aid from the Government of Japan"—for 1983-84, Grant for purchase of the microfilm equipment/services for the purpose of preserving the historical records of India.

IV (ii) The amount referred to above should be deposited in cash to the credit of the Government either in the Reserve Bank of India, New Delhi indicating Code No. 5130000009 on the right hand corner of the challan or in the State Bank of India, Tis Hazari, Delhi or if this is not possible, should be remitted by means of a demand draft obtained from any branch of the State Bank of India or its subsidiaries or any one of the Nationalised Banks (Drawer) drawn on and made payable to the State Bank of India, Tis Hazari Branch, Delhi-6 (Drawee and Payee) for credit to Government account as contemplated in Public Notices No. 184-ITC(PN)|68 dated 30-8-1968, No. 233-ITC(PN)|68 dated 24-10-1968 and No. 132-ITC(PN)|71 dated 5-10-1971, No. 74-ITC(PN)|74 dated 31-5-1974 and No. 103-ITC(PN)|76 dated 12-10-1976.

IV (iii) The concerned bank in India shall also furnish such additional deposit in the same manner stipulated above as may be requested by the Government of India on account of service charges within seven days after such a demand is made by the Government. While filling in the various columns in the Challan it should be ensured by the Importers/their bankers that the information prescribed in para 2 of Public Notice No. 132-ITC(PN)|71 dated 5th October 1971 and also in Public Notice No. 74-ITC(PN)|74 dated 31-5-1974 read with Public Notice No. 103-ITC(PN)|76 dated 12-10-1976 is invariably indicated in the column "full particulars of remittances and authority (if any)" of the challan. The following particulars should invariably be furnished in the Treasury Challans :

- Ministry of Finance 'A/P' (Authorisation to Pay) No. and Date.
- Amount to Yen Currency in respect of which deposits are to be made together with rate of conversion adopted.
- Date of payment to the Japanese supplier.
- The amount of interest paid and the period for which it has been calculated.
- Total amount deposited.

(Interest is to be calculated for the period from the date of payment to the Japanese supplier upto and inclusive of the date of deposit of rupee equivalents into Government Account).

Thereafter the Treasury Challans evidencing the rupee deposit should be sent by registered post to the CAA&A indicating reference to the A|P issued by him and also enclosing copies of invoice and shipping documents.

Note.—Importer's Bank in India should ensure that the rupee deposits are invariably made within 10 days of the receipt of the advice of payment and negotiable shipping documents from the Bank of India, Tokyo and that the CAA&A, Ministry of Finance (DEA), New Delhi is informed immediately thereafter.

IV (iv) The concerned bank in India should also endorse the amount of rupee deposits on the exchange control copy of the licence and send the requisite "S" Form to the Reserve Bank of India, Bombay.

Section V: Miscellaneous provisions

V (i) Reports on the utilisation of the Grant Aid

The importer should send a monthly report after the A|P has been issued regarding shipments and payments made there against and about the balance left, to the Controller of Aid Accounts and Audit, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, UCO Bank Building, Parliament Street, New Delhi.

The importer should apprise the supplier of any special provisions in the import of goods under this Grant Aid which may effect the suppliers in carrying out the transaction.

V (iii) Disputes

It should be understood that the Government of India will not undertake any responsibility for dispute, if any, that may arise between the importer and the suppliers. The conditions to be fulfilled by the supplier before payment by the Bank of India, Tokyo must be clearly spelt out by the importer in Annexure I under "Terms of Payment". Provision dealing with a settlement of disputes be included in the condition of contract.

V (iv) Future Instructions

The importer shall promptly comply with any direction, instructions or orders issued by the Government of India from time to time regarding any and all matter arising from or pertaining to the imports and for meeting all obligations under the Grant Aid for 1983-84 from Japan.

V (v) Breach or violation

Any breach or violation of conditions set forth in the above clauses will result in appropriate action under the Imports and Exports (Control) Act.

V (vi) List of Annexures

Annexure I—Request for issue of A|P

Annexure II—Form of A|P.

Annexure I

REQUEST FOR ISSUE OF THE AUTHORISATION TO PAY No.

To

The Controller of Aid Accounts & Audit.

Ministry of Finance,

Department of Economic Affairs,

UCO Bank Building, 1st Floor.

Parliament Street, New Delhi-110001.

Subject:—Import of microfilm equipment and services necessary for the transportation of the equipment to ports in India from Japan under the Japanese Grant Aid of Yen 20 Million for 1983-84.

Sir,

In connection with the import of above mentioned equipment from Japan under the above mentioned Grant Aid, we furnish the following particulars to enable you to issue the A|P to the Bank of India, Tokyo in favour of the Japanese Supplier concerned:—

- (a) Name and address of Indian importer.
- (b) Number, date and value of the import licence and date upto which it is valid.
- (c) Method of procurement whether it is based on direct purchase or limited open tendering in which case it should be indicated whether the contract has been awarded on the basis of technically suitable offer with reason, if any.
- (d) Brief description of the goods.
- (e) Origin of the goods.
- (f) Gross C&F value of contract (in Yen).
- (g) Amount of India agent's commission (in Yen), if any, payable in Indian rupees.
- (h) Net C&F value (in Yen) for which the A|P is required.
- (i) Name and date of the contract with Japanese Suppliers.
- (j) Name and address of the Japanese Supplier and attach an eligibility certificate (in duplicate).
- (k) Payment terms and probable dates on which payments under the contract will fall due.
- (l) Expected date of completion of deliveries.

- (m) Documents to be presented at the time of payment to Bank of India, Tokyo (indicating No. of sets of each and their disposal).
- (n) Shipment instructions (indicate if transhipment/partshipment permitted or not permitted).
- (o) Name and Address of the Importer's bank of India.
- (p) Undertaking by the importer :—“We hereby undertake to make full and correct deposit of the rupee equivalent etc., of the payment made to the foreign supplier in the manner and at the rate prescribed by Government. The deposits will be made promptly before taking delivery of each consignment of the goods (material imported). In case of payments for services of foreign nationals, the deposits will be made as soon as the relevant invoices of the foreign suppliers are approved by us and the payments made to the supplier.”

Yours faithfully,

ANNEXURE-II

No. F.

Government of India
Ministry of Finance
Department of Economic Affairs
New Delhi, the

To

The Bank of India,
Tokyo Branch,
Tokyo (Japan).

Subject:—Import of microfilm equipment and services necessary for the transportation of the equipment to ports in India from Japan under Japanese Grant Aid of Yen 20 million for 1983-84. Issue of Authorisation to Pay.

Dear Sirs,

In accordance with the terms and conditions of the agreement dated entered into with your Bank, you are hereby authorised to pay an amount not exceeding Yen to M/s as per details given in the appendix.

2. Please advise the Supplier of the fact of receipt of this Authorisation to Pay (A|P) and endorse a copy of this advice to the Government of Japan, importers' Bank, Embassy of India, Tokyo and this Ministry.

3. Payments to the suppliers in terms of the A|P will be made on the basis of shipping documents as indicated in the Appendix.

4. Banking charges including charges for handling documents and charges of Overseas Suppliers,

Bankers if any, payable to you by the importer, will be settled directly by the importer's bank.

5. As and when any payment is made by you on the basis of shipping documents presented by the Japanese supplier, an advice in the prescribed form should be sent to this Ministry and the importer's bank.

6. No amendment to this A|P may be advised in the absence of a specific authority from this Ministry.

7. This A|P will remain valid upto.....

Yours Faithfully,
(Accounts Officer)

Copy forwarded to :—

1. Importer with reference to their letter No..... dated

They are requested to arrange to deposit through their Bankers, the rupee deposits etc. at the prescribed rate and manner, before taking delivery of the negotiable documents from the Bankers. In case due to exceptional circumstances delivery of goods is obtained directly from the Customs and Port authorities without furnishing the original shipping documents, the deposits should be made before taking the delivery. In the case of payments for services rendered by foreign Nationals, the deposits should be made as soon as the relevant invoices are approved for payment. Failure to make the deposits promptly and correctly may entail action as mentioned in the Licensing conditions.

2. Importer's Banker..... They are requested to arrange to deposit the rupee equivalent of the Yen payment to the Japanese suppliers on receipt of documents from the Bank of India, Tokyo Branch. The rupee equivalent of amount disbursed to the suppliers will have to be calculated by applying the composite rate of conversion as prevailing on the date of payment to Japanese suppliers in accordance with the Public Notice No.8-ITC(PN)|76 dated 17-1-1976 or such other Public Notices as may be issued from time to time. Interest 12 per cent per annum for the first thirty days and at the rate of 18 per cent annum for the period excess thereof reckoned for the period between the date of payment to the supplier and the date on which the rupee equivalents are deposited into the Government account, is required to be deposited into the Government of India account in terms of Public Notices No. 31-ITC (PN) |83 dated 10-8-1983. The interest is payable for both the days i.e. the day on which payment is made to the Japanese Supplier and also the date on which rupee deposit is made into Government account. (Any change in this rate will be intimated if and when made). It should be ensured that these deposits are made before the original set of import documents are handed over to the importer for Customs Clearance.

These amounts should be deposited either with the RBI, New Delhi indicating Code No. 5130000009 on the right hand corner of the Challan or in the S.B.I., Tis Hazari, Delhi or remitted by means of Demand Draft obtained by them from any Branch of the S.B.I or its subsidiaries or any one of the Nationalised Banks (Drawer) drawn on and made payable to the S.B.I., Tis Hazari, Delhi-6 (drawee and Payee). In this connection their attention is also invited to the provisions of the Public Notices No. 233-ITC(PN)68 dated 24-10-1968, No. 132-ITC(PN)71 dated 5-10-1971, No. 74-ITC(PN)74 dated 31-5-1974 and 103-ITC(PN)76 dated 12-10-1976. The head of account to be credited is 'K-Deposits & Advances-843-CIVIL Deposits-Deposits for purchases etc. abroad-Purchases under Grant Aid from Govt. of Japan for 1983-84 under detailed head 'Y 20 million grant aid for purchase of the microfilm equipment|services for the purpose of preserving the historical records of India.

One copy of the challan in orginal, in cases where the rupee equivalents are credited in cash at the RBI, New Delhi or the SBI, Tis Hazari, Delhi as prescribed in Public Notice No. 132-ITC(PN)71 dated 5-10-1971 should be sent by them to the address given below alongwith a forwarding letter giving full

details of the advice notes received from the Bank of India, Tokyo Branch.

The Controller of Aid Accounts & Audit, Ministry of Finance (Department of Economic Affairs), 1st Floor, UCO Bank Building, Parliament Street, New Delhi-110001.

In cases where the rupee equivalents are remitted by means of demand drafts as laid down in the Public Notice dated 24-10-1968 mentioned above, intimations thereof should be sent to the address given above. In all cases, full particular of the rupee equivalents deposited alongwith the amount of interest paid and the period for which interest has been calculated should be furnished to this Department.

The banking charges, of the Bank of India, Tokyo Branch, including charges of the Overseas suppliers bankers, if any, should be settled directly between the Indian Bank and the Bank of India, Tokyo Branch.

4. Embassy of India, Tokyo.
5. The Under Secretary (IA), Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, New Delhi.

Accounts Officer